



## झारखंड और तमलिनाडु द्वारा उच्च रॉयल्टी दर की माँग पर परमाणु ऊर्जा वभाग ने जताई असहमति

### चर्चा में क्यों?

परमाणु ऊर्जा वभाग ने रॉयल्टी दर तथा 'उपभोग नरिपेक्ष करिया' (dead rent) को ये कहते हुए संशोधन करने से इंकार कर दिया किये 'सामरिक खनजि' (strategic minerals) हैं तथा इनकी उपलब्धता भारत में कम है। DAE के अनुसार, चूँकि रॉयल्टी उत्पादित खनजिों पर देय है और रॉयल्टी की मात्रा 'उपभोग नरिपेक्ष करिया' की तुलना में अधिक है, इसलिये उपभोग नरिपेक्ष करिया की मौजूदा दरों को बना करिसे संशोधन के बनाए रखा जा सकता है।

### महत्त्वपूर्ण बडि

- मंत्रालय ने वभिन्न खनजिों पर रॉयल्टी शुल्क तथा उपभोग नरिपेक्ष करिया के संशोधन पर वचिर करने के लिये एक अलग उप-समूह का गठन कया है।
- इस उप-समूह की गतविधियों का दशिया-नरिदेशन केवल परमाणु ऊर्जा वभाग (Department of Atomic Energy- DAE) द्वारा कया जाएगा।
- खान और खनजि (वकिस और वनियिमन) संशोधन अधनियिम, 2015 के तहत, प्रत्येक जलि में (जहाँ खनन कया जाता है), खनन परचालन से प्रभावति स्थानीय आबादी को लाभ पहुँचाने के एकमात्र उद्देश्य से DMF (District Mineral Foundation) का गठन कया गया।
- अन्वेषण को बढावा देने के लिये 2015 के खनन कानून के तहत, NMET (National Mineral Exploration Trust) का भी गठन कया गया था।
- खनन पट्टा मालकिों को DMF के साथ-साथ NMET को भी अपनी रॉयल्टी के अनुपात में एक नश्चिति राशा देनी पडती है।
- DMF तथा NMET को भुगतान की गई राशा रॉयल्टी शुल्क तथा उपभोग नरिपेक्ष करिया में शीर्ष पर है।
- सतिंबर 2017 तक तमलिनाडु के पास 51 भंडारों में कुल 2.4 मिलियन टन मोनाज़ाइट उपलब्ध था। झारखंड के पास केवल एक भंडार में 0.21 मिलियन टन मोनाज़ाइट है।
- परमाणु खनजि अन्वेषण एवं अनुसंधान नदिशालय (AMD) के अनुसार, झारखंड में 67.7 हज़ार टन ट्राईयूरेनियम ऑक्टोऑक्साइड (जो यूरेनियम का एक अयस्क है) का भंडार है।
- AMD, जो DAE के अधीन कार्य करता है, के पास यूरेनियम, थोरियम, नाइओबियम, टैंटलम, बेरलियम, लथियम, ज़रिफोनियम तथा टाइटेनियम जैसे परमाणु खनजिों की पहचान करने तथा मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है।
- भारत ने इससे पहले खनजिों पर रॉयल्टी कर तथा 'उपभोग नरिपेक्ष करिया' में संशोधन 1 सतिंबर, 2014 को कया था।
- 2014 की अधसिचना के अनुसार, एक खनकि को मोनाज़ाइट के लिये 125 रूपए प्रति टन का रॉयल्टी देनी पडती है।
- यूरेनियम रॉयल्टी दर 'यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Uranium Corporation of India Ltd - UCIL) द्वारा प्राप्त वार्षकि मुआवज़े की राशा का दो प्रतिशत' होता है, जसि बाद में DAE द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकडों के आधार पर राज्यों के बीच वभिजति कया जाता है।
- UCIL जो कसिार्वजनकि क्षेत्र का एक उपक्रम है, एक मात्र कंपनी है जसि भारत में यूरेनियम खनन का अधिकार प्राप्त है।

### उपभोग नरिपेक्ष करिया (Dead Rent)

'उपभोग नरिपेक्ष करिया' एक नश्चिति राशा है, जसिका भुगतान खनकि द्वारा खान से नकिले खनजि की मात्रा के बदले कया जाता है।

### रॉयल्टी शुल्क

जो भुगतान वशिष रूप से कसिी वयकतिया संस्थान द्वारा कसिी संपत्ति, पेटेंट, फ्रैंचाइज़ी, कॉपीराइट या प्राकृतकि सुवधि के लिये मालकि को दी जाती है, ताका उसका उपयोग वो अपने लाभ के लिये कर सके, रॉयल्टी कहलाती है।

### परमाणु ऊर्जा वभाग

परमाणु ऊर्जा वभाग (DAE) की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत दिनांक 3 अगस्त, 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा वभाग की संकल्पना प्रौद्योगिकी, अधिकि संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाना है।

